नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सदन में आकर दें जवाब : खरगे

4 हथकरघा : विकसित भारत के भविष्य की बुनाई

9 वाहनों की खुदरा बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड

11 ओडिशा, पंजाब, एमपी सेमीफाइनल में

गांव-गांव अब बनेगी गैस

गोबरधन योजना को कैबिनेट की मंजूरी

23731 करोड़ की बायोएनर्जी योजना 'गोबरधन' को मंजूरी

2035-36 वित्त वर्ष तक लागू रहेगी भारत की यह ऊर्जा योजना

नई दिल्ली, 06 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना 'गोबरधन' को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेष, गोबर, शहरी जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को संपीड़ित बायोगैस, जैविक खाद और ग्रामीण आय के स्रोत में बदलना है.

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी और भारत की ऊर्जा व्यवस्था में

संपीड़ित बायोगैस को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करेगी. सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से देश में सीबीजी उत्पादन को करीब 10 गुना बढ़ाना, निजी निवेश आकर्षित करना और सर्कुलर बायोइकोनॉमी को मजबूत करना है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार, स्थिर मूल्य, पूंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, ऋण सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, यह योजना किसानों, सहकारी समितियों, फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगी. साथ ही कृषि अवशेष, गोबर और शहरी जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जैविक खाद के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार का कहना है कि गोबरधन योजना को कैबिनेट की मंजूरी योजना ऊर्जा सुरक्षा, 'वेस्ट टू वेल्थ', आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

लेन कॉरिडोर के लिए 8,970 करोड़ रुपए होंगे खर्च

1 असम और अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा बेहतर संपर्क

2 आठ पीएम गति शक्ति आर्थिक केंद्रों से जुड़ेगा कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के 135.871 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले पहुंच-नियंत्रित गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के तहत निर्मित-संचालन-स्थानांतरण (टोल) मोड पर विकसित होने वाली इस परियोजना पर 8,970.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. परियोजना में 15.11 किलोमीटर लंबे मंगलदोई बाईपास को छोड़कर बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक चार लेन मार्ग का निर्माण शामिल है.

परियोजना के तहत तेजपुर बाईपास पर 4.9 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की जाएगी. इसे भारतीय वायु सेना के समन्वय से अंतिम रूप दिया गया है. यह सुविधा रणनीतिक और आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. बैहाटा चारियाली, सिपाझार, खारूपेटिया, ढेकियाजुली और तेजपुर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए कुल 58.7 किलोमीटर लंबाई के पांच प्रमुख बाईपास बनाए जाएंगे. इससे आबादी वाले इलाकों में भारी वाहनों का दबाव कम करने और यात्रा को सुगम बनाने में मदद मिलेगी. परियोजना में 15 बड़े पुल और 30 छोटे पुल बनाने का प्रावधान है. इसके अलावा 19 फ्लाईओवर और तेजपुर बाईपास पर एक हाथी अंडरपास भी बनाया जाएगा. नियंत्रित पहुंच वाले राजमार्ग पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 46 अंडरपास भी विकसित किए जाएंगे. चार लेन वाले नियंत्रित पहुंच मार्ग के साथ 19 फ्लाईओवर के लिए कुल 210 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा.

सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट

आवारा कुत्तों की याचिकाओं पर सुनवाई 14 को

जबलपुर, 06 अगस्त. आवारा कुत्तों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किये गये निर्देश के बाद की गयी कार्यवाही के संबंध में सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गयी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर 14 अगस्त को सुनवाई के निर्देश जारी किये है.

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के आंतक को गंभीरता से लेते हुए डॉग बाइट और रेबीज की ब ?ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी संस्थानों जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे

स्टेशन शामिल हैं को चिन्हित करते हुए आवारा कुत्तों का टीकाकरण या नसबंदी करने के निर्देश दिये थे. सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को इन जगहों का समय-समय पर निरीक्षण करने निर्देशित किया था, जिससे कुत्ते अपना घर न बना सकें. इसके अलावा जिन कुत्तों को रेबीज है या रेबीज होने का संदेह उन्हें शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिये थे.

सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करने के निर्देश दिये थे. हाईकोर्ट पूर्व में भोपाल में कुत्ते के द्वारा बच्ची पर हमला किये जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में कर रहा था. इसके आवारा कुत्ते के संबंध में अन्य याचिकाएं भी दायर की गयी थी. युगलपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा -निर्देशों का पालन करते हुए नगरीय निकाय तथा गृह विभाग को सार्वजनिक स्थलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी करने के निर्देश दिये है. युगलपीठ ने कार्यवाही के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे.

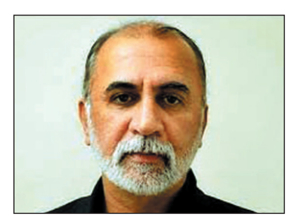

तरुण तेजपाल को हुई 10 साल की सजा

मुंबई/पणजी. करीब 13 वर्ष पुराने चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान होटल की लिफ्ट में 7 और 8 नवंबर की रात तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया.

रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर की बात

नई दिल्ली, 06 अगस्त. संसद के मानसून सत्र के बीच केंद्र सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयकों पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बातचीत कर इन विधेयकों पर कांग्रेस का समर्थन मांगा.

सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक को समर्थन मिलने से महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता आसान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि महिला आरक्षण लागू नहीं होता है तो महिलाओं के बीच नाराजगी बढ़ सकती है. हालांकि राहुल

परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों पर की चर्चा

गांधी ने सरकार को तत्काल समर्थन का आश्वासन नहीं दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस विषय पर पहले अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से चर्चा करेगी. इसके बाद सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा और फिर पार्टी अपना आधिकारिक रुख सरकार को बताएगी.

बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण

- 4,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम
- ओडिशा की चांदीपुर से भारत ने दिखाई ताकत

नई दिल्ली, 06 अगस्त। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का गुरुवार को सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। सामरिक बल कमान की देख-रेख में किये गये परीक्षण के दौरान सभी संचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई।

यह मिसाइल 4,000

किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और एक टन वजनी परमाणु हथियार ले जा सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल से देश की रणनीतिक रक्षा और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी।

1.28 करोड़ का विदेशी सोना जब्त

- एयरपोर्ट कर्मचारी समेत पांच गिरफ्तार
- अबूधाबी से आए यात्री और नेटवर्क से जुड़े लोग रडार पर

नव भारत न्यूज

इंदौर, 6 अगस्त. डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की इंदौर जोनल यूनिट ने विदेशी सोना तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.28 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है. एजेंसी ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक एयरलाइन कर्मचारी भी शामिल है.

जांच में सामने आया है कि तस्करों ने सोने को सामान्य धातु की चूड़ियों का रूप देकर सीमा शुल्क जांच से बचाने की योजना बनाई थी.

डीआरआई सूत्रों का कहना है कि 4 अगस्त को अबूधाबी से इंदौर पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 248 से यह सोना लाया गया था. जांच के दौरान एजेंसी ने 1000.20 ग्राम विदेशी मूल का सोना बरामद किया. इसकी कीमत करीब 1.28 करोड़ रुपए आंकी गई है. मामले में डीआरआई ने संजय मुंजे उम्र 48 साल, अमन गहलोत उम्र 30 साल, गोविंद पोरवाल उम्र 48 साल, वासुदेव बरनाले उम्र 32 साल और अजय कुमार सेन उम्र 56 साल को गिरफ्तार किया है. बुधवार को सभी आरोपियों को विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया, जहां डीआरआई की ओर से अधिवक्ता चंदन ऐरन ने पक्ष रखा. न्यायालय ने आरोपियों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जांच में सामने आया कि तस्करी के लिए आरोपियों ने पहले से पूरी योजना तैयार कर रखी थी. सोने को इस तरह तैयार किया था कि वह सामान्य धातु की चूड़ियों... ▶ शेष पेज 12 पर

और कौन-कौन जुड़े हैं....?

डीआरआई यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क से और कौन लोग जुड़े हैं और क्या इससे पहले भी इसी तरीके से विदेशी सोने की तस्करी की गई है. पूरे मामले में डीआरआई अधिकारियों का कहना है कि विदेशी सोना तस्करी मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

नीरज डांगी राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक नियुक्त

नई दिल्ली. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक (व्हिप) नियुक्त किया है. कांग्रेस संसदीय दल ने गुरुवार को यहां एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री डांगी को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक बनाया गया है.

गुस्ताखी माफ

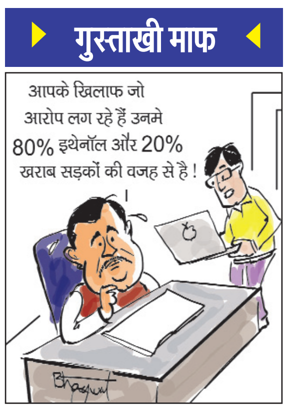

पुरानी बारूदी सुरंग में विस्फोट में दो जवान घायल

जम्मू. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास बुधवार दोपहर पुरानी जंग लगी बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब सेना के जवान पुरानी जंग लगी सुरंगों को नष्ट कर रहे थे. उन्होंने बताया कि घायल जवानों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सेना के राजौरी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जेन-जी पर संघ का बड़ा दांव

जेन जी की नाराज़गी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटा संघ

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली,06 अगस्त .संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जेन जी व छात्र आंदोलन के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है.

कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख ने सोची-समझी बहुआयामी रणनीति के तहत जहां एक तरफ केंद्र सरकार को आईना दिखाते हुए मौजूदा असंतोष के बीच वैचारिक रक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास किया है वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा युवाओं के मुद्दों पर लगातार गढ़े जा रहे आक्रामक और तीखे नैरेटिव की काट खोजने का प्रयास किया है.

उल्लेखनीय है कि मुंबई के युवा सम्मेलन में सरसंघचालक का यह कहना कि आंदोलित युवाओं को देश-विरोधी मानना गलत है और उनकी शिकायतें पूरी तरह जायज हैं, भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है.

राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि उक्त वक्तव्य सत्ता की नीतियों से पूर्ण सहमति का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालातों की एक व्यावहारिक और साहसिक स्वीकारोक्ति है. संघ भली-भांति समझता है कि पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली की खामियों के कारण देश की नई पीढ़ी के भीतर एक गहरा असंतोष पनप रहा है. इस गुस्से को केवल राष्ट्रवाद के पारंपरिक चश्मे से देखना या बलपूर्वक दबाना आत्मघाती साबित हो सकता है. संभवत: इसीलिए आंदोलनों को लोकतंत्र में सहमति बनाने का जरिया... ▶ शेष पेज 12 पर

जेन-जी से बातचीत ▶ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले- शिक्षा व्यवसाय नहीं जीवन की जरूरत, शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत बजट जरूरी

संवादहीनता सरकार की सबसे बड़ी चूक

मुंबई, 06 अगस्त. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी विवाद या असहमति का सबसे प्रभावी समाधान संवाद और बातचीत से ही संभव है.

मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार और समाज समय रहते संवाद करें तो

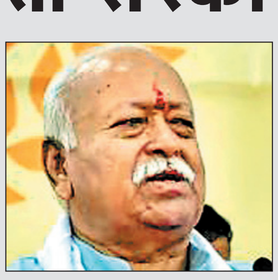

आंदोलनों की आवश्यकता काफी हद तक कम हो सकती है. लेकिन यह भी जरूरी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण और व्यवस्था सुधार के उद्देश्य से हों. उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आरक्षण पर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर कि सलाह मान्य है। जब तक समाज से भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा. युवाओं पर भरोसा जताते हुए मोहन भागवत ने कहा कि सरकार से बड़ी चूक हुई है जेन जी से पहले ही बात करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि यदि युवा आवाज उठा रहे हैं तो उसकी वजह समझने की जरूरत है. शिक्षा व्यवसाय नहीं जीवन की जरुरत है. इसलिए सरकार को शिक्षा में सुधार के लिए 6 प्रतिशत बजट करना चाहिए.

पाकिस्तान भी ऐतिहासिक रूप से भारत की का हिस्सा है

पाकिस्तान को लेकर पूछे गए प्रश्न पर भागवत ने कहा कि भारत किसी का नुकसान नहीं चाहता और उनका मानना है कि पाकिस्तान भी ऐतिहासिक रूप से भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है. उन्होंने हिंसा के संबंध में विस्तृत जानकारी न होने की बात कहते हुए कहा कि किसी भी तनाव का समाधान अंतत: संवाद से ही निकल सकता है.

शिक्षा कभी भी केवल कमाई का माध्यम नहीं बननी चाहिए

शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि शिक्षा कभी भी केवल कमाई का माध्यम नहीं बननी चाहिए. उन्होंने शिक्षा के लिए सकल बजट का छह प्रतिशत निर्धारित करने की वकालत करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है. महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए.